ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

निर्धारित तत्वों पर सरकार द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रबंधन का एक अध्ययन

अनिता, शोधार्थी (अर्थशास्त्र) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर
डॉ. रणधीर सिंह, सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर

परिचय

आर्थिक प्रबंधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर, विकसित और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, नीतियों और विनियमों का समूह है। श्निर्धारित तत्वश से तात्पर्य उन विशिष्ट क्षेत्रों, कारकों, या संकटों से है, जिन पर नियंत्रण, सुधार या प्रोत्साहन के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति नियंत्रण, राजकोषीय घाटा प्रबंधन, बेरोजगारी उन्मूलन, या किसी विशेष उद्योग को बढ़ावा देना। यह शोध पत्र सरकार द्वारा इन निर्धारित तत्वों पर लगाए गए आर्थिक प्रबंधन की प्रकृति, प्रभावशीलता और चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत जैसे विकासशील देश में, सरकारी प्रबंधन का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण को भी सुनिश्चित करना होता ळें

साहित्य समीक्षा

इस खंड में पिछले शोधकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों और सरकारी रिपोर्टों के कार्यों का संक्षिप्त विश्लेषण किया जाएगा, जो सरकारी आर्थिक प्रबंधन और संबंधित तत्वों पर किए गए हैं।

- सरकारी हस्तक्षेप के सिद्धांत (Theories of Government Intervention): कीनेसियन अर्थशास्त्र (Keynesian Economics) जैसे सिद्धांतों का अवलोकन जो आर्थिक अस्थिरता को कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं।
- राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ (Fiscal and Monetary Policies): पूर्व में अपनाई गई राजकोषीय (कर और व्यय) और मौद्रिक (ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति) नीतियों की सफलता और असफलता का मूल्यांकन।
- क्षेत्र–विशेष अध्ययन (Sector&Specific Studies): कृषि, बैंकिंग, या औद्योगिक जैसे निर्धारित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं (जैसेरू पीएम किसान, जीएसटी, एनपीए प्रबंधन) के कार्यान्वयन और उनके दीर्घकालिक प्रभावों से संबंधित शोध कार्यों का सारांश।
- आर्थिक असमानता और प्रबंधन (Economic Inequality and Management): उन अध्ययनों की समीक्षा जिन्होंने बताया है कि सरकारी प्रबंधन ने आर्थिक असमानता और गरीबी उन्मूलन को किस हद तक प्रभावित किया है।
- निष्कर्षः साहित्य समीक्षा से यह पता चलता है कि सरकारी आर्थिक प्रबंधन का प्रभाव संदर्भ–विशिष्ट (Context & Specific) होता है और अक्सर जटिल होता है। पूर्व के शोधों में कुछ क्षेत्रों पर प्रबंधन की सफलता को दर्शाया गया है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे वर्तमान शोध के लिए एक शोध गैप की पहचान होती है।

शोध के सोपान

यह शोध निम्नलिखित चरणों का पालन करेगा:

समस्या का चयन और निरूपण: श्निर्धारित तत्वों पर सरकारी आर्थिक प्रबंधनश का चयन करना।
उद्देश्यों और परिकल्पना का निर्धारणरू शोध के लक्ष्यों और अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट करना।
साहित्य समीक्षारू विषय से संबंधित पूर्व के कार्यों का अध्ययन करना।
शोध प्रविधि (Reserch Methodology) का निर्धारण: गुणात्मक (Qualitative) औरध्या मात्रात्मक (Quantitative) दृष्टिकोण तय करना।
डेटा संग्रहरू सरकारी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षणों, बजट दस्तावेजों और सांख्यिकीय डेटा को इकट्ठा करना।
डेटा विश्लेषण और व्याख्या: एकत्र किए गए डेटा का सांख्यिकीय या विषयगत विश्लेषण करना।
निष्कर्ष और सुझावरू शोध के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और नीतिगत सुझाव देना।
शोध पत्र लेखन: संपूर्ण कार्य को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना।

शोध गैप

पूर्व के अधिकांश अध्ययन सरकारी प्रबंधन के किसी एकल पहलु (जैसे केवल मौद्रिक नीति या केवल राजकोषीय नीति) पर केंद्रित रहे हैं। वर्तमान शोध गैप यह है कि विभिन्न निर्धारित तत्वों (जैसेः मुद्रास्फीति,

राजकोषीय घाटा और निर्यात संवर्धन) पर एक साथ लागू किए गए सरकारी आर्थिक प्रबंधन के एकीकृत और परस्पर जुड़े प्रभावों का व्यापक विश्लेषण कम उपलब्ध है। यह शोध विभिन्न तत्वों पर प्रबंधन के सह–संबंध और एक तत्व पर प्रबंधन के अन्य तत्वों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझने का प्रयास करेगा।

शोध औचित्य

यह शोध वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है।

नीति–निर्माण में सहायतारू यह नीति निर्माताओं को विभिन्न आर्थिक तत्वों के बीच जटिल संबंधों को समझने में मदद करेगा, जिससे वे अधिक प्रभावी और संतुलित नीतियां बना सकेंगे।

जवाबदेही (Accountability): यह सरकारी प्रबंधन की प्रभावशीलता का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करके, सरकार की आर्थिक जवाबदेही को बढ़ाएगा।

शैक्षणिक योगदान: यह शोध छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक व्यापक संदर्भ बिंदु प्रदान करेगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था और लोक प्रशासन में रुचि रखते हैं।

उद्देश्य

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैंरू

निर्धारित तत्वों (जैसे, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राजकोषीय स्वास्थ्य) पर सरकारी आर्थिक प्रबंधन की प्रकृति और दायरे का विश्लेषण करना।

पिछले पाँच वर्षों में इन तत्वों पर लागू की गई प्रमुख सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

सरकारी प्रबंधन के कारण इन तत्वों में आए दीर्घकालिक परिवर्तनों की पहचान करना।

आर्थिक प्रबंधन के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का पता लगाना।

बेहतर आर्थिक परिणामों के लिए सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

मुख्य परिकल्पना (\text{H}_1) :

निर्धारित तत्वों पर सरकार द्वारा लागू किया गया आर्थिक प्रबंधन (विशेषकर राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां) अल्पकालिक स्थिरता प्राप्त करने में प्रभावी रहा है, लेकिन दीर्घकालिक संरचनात्मक समस्याओं (जैसे कि बेरोजगारी) के समाधान में इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है।

शून्य परिकल्पना (\text{H}_0):

निर्धारित तत्वों पर सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक प्रबंधन और अल्पकालिकध्दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

महत्व

यह शोध सैद्धांतिक (Theoretical) और व्यावहारिक (Practical) दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

सैद्धांतिक महत्वरू यह सरकारी प्रबंधन के विभिन्न मॉडलों के भारतीय संदर्भ में अनुप्रयोग और अनुकूलन को समझने में मौजूदा ज्ञान में वृद्धि करेगा।

व्यावहारिक महत्वरू यह विशेष रूप से उन नीतियों को उजागर करेगा जो विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल या असफल रही हैं, जिससे भविष्य के नीति–निर्माण के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह विभिन्न हितधारकों (उद्योग, शिक्षाविद, और आम जनता) को सरकारी आर्थिक फैसलों के निहितार्थों को समझने में सक्षम बनाएगा।

निष्कर्ष

शोध के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार द्वारा निर्धारित तत्वों पर लगाए गए आर्थिक प्रबंधन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई वैश्विक और घरेलू झटकों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, राजकोषीय प्रबंधन ने ब्व्टप्व–19 जैसे संकटों के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। हालांकि, मुख्य परिकल्पना (\text{H}_1) को आंशिक समर्थन मिलता हैः जबकि मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे जैसे अल्पकालिक तत्वों का प्रबंधन प्रभावी रहा है, लेकिन बेरोजगारी, आय असमानता और कृषि उत्पादकता जैसे दीर्घकालिक और संरचनात्मक तत्वों पर वांछित सफलता अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। प्रभावी परिणामों के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन नीतियां अधिक लचीली, डेटा–आधारित और अंतर–क्षेत्रीय समन्वय पर केंद्रित हों।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

ग्रंथ सूची

- भारत सरकार, (2024). आर्थिक समीक्षा (Economic Survey). वित्त मंत्रालय.
- RBI (भारतीय रिजर्व बैंक). (समय–समय पर). मौद्रिक नीति रिपोर्टें.
- कौशिक, आर. (2021). भारतीय अर्थव्यवस्थारू विकास और चुनौतियाँ. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- डॉ. सिंह, ए. (2020). ष्भारत में राजकोषीय प्रबंधन और इसका प्रभावरू एक आलोचनात्मक विश्लेषणष् जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. वॉल्यूम 15, अंक 2.
- विश्व बैंक की रिपोर्टें और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के शोध पत्र।

SHRADHA EDUCATIONAL ACADEMY